

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) and (b). There is generally no delay in berthing of vessels carrying cement at the major ports. Sometimes delay is caused due to bunching in arrivals. No vessel carrying cement was waiting for berth at any of the major ports on 27-3-1978. No foreign exchange remittance towards demurrage has so far been necessary to any overseas party.

(c) Does not arise.

कानपुर स्थित थार्डेन्स इन्वियमेंट कंपनी के लिए मशीनों का आयात

5707. श्री हरचोबिन्द बर्वा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित थार्डेन्स इन्वियमेंट कंपनी में जेट-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विदेशों से मशीनों का आयात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा कितने मूल्य की मशीनों का आयात किया गया है ;

(घ) क्या ये मशीनें अभी तक अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० ओर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय ब्रह्मचरिणी नियम को 1978 में बाटा

5708. श्री स्वप्न लाल कुर्ब: क्या नौबहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ब्रह्मचरिणी नियम को इस वर्ष भी बाटा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण हैं ?

नौबहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) भारतीय नौबहन नियम को, अपने स्थापना काल से 1976-77 तक कोई घाटा नहीं हुआ है । परन्तु, संकेत ऐसे हैं कि इसे 1977-78 में बाटा होगा । चुंकि लेखों को, अभी तक अंतिम रूप देकर लेखा परीक्षा नहीं की गयी है, अतः कितना घाटा होगा, मानस नहीं है ।

प्रत्यागित बाटे का मुख्य कारण विश्व भर में बाडा दरों में बड़ी मंदी है । इसके अलावा, भारतीय नौबहन नियम को अद्यतन और लक्ष्मी के लिए संवर्धनात्मक और यात्री सेवाओं का भार सीपा गया है । यात्री सेवाओं के मामले में, सरकार के कहने पर लागत से कम दरें प्राप्त की जाती हैं ।

Punitive Fine for Excesses on Harijans

5709. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Central Government has advised the State Governments to levy punitive fine on those committing excesses on Harijans, repeatedly; and

(b) if so, the details regarding the response of the States in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). Provision for imposition of fines, imprisonment etc. for offences exists under the normal laws. Provision also exists for imposing collective fines under the Protection of Civil Rights Act, 1958, empowering the State Governments to take necessary action in this regard. The Central Government has not issued any instructions on the subject.